>

Title: Need to sanction financial assistance for electrification of all villages having a population of 300 people and above in Chitrakoot in Banda Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्री आर.के.ि ंसह पटेल (बांदा): सभापति जी, जब हम चुनाव में जाते हैं तो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का वचन देकर आते हैं। सड़क, बिजली और पानी को पूरा करने के लिए सरकार भी वचनबद्ध है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत द्वितीय फेज को पूरे देश सहित मेरे क्षेत्र बांदा-चित्रकूट को पूरा करने के लिए इसी सदन में माननीय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री शिंदे जी थे। मैंने नियम 377 के तहत मैंने एक मामले को उठाया था। उन्होंने लिखित उत्तर दिया था कि वÂर्ष 2014 तक द्वितीय फेज लेकर 300 से अधिक आबादी के जितनी बसावटें हैं उनका विद्युतीकरण कर दिया जाएगा।

महोदय, खेद का विÂषय है और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वर्ष 2010-11 में मेरे पास माननीय ऊर्जा मंत्री जी का लिखित जवाब आया था कि वर्ष 2014 तक पूरा कर देंगे। वर्ष 2014 आने वाला है और ढाई साल बीत चुके हैं, हमने माननीय मंत्री जी के वायदे के अनुसार मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से वायदे कर लिए हैं कि जल्दी से जल्दी विद्युतीकरण हो जाएगा। अगर माननीय मंत्री जी और सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर मैं इसी सदन में अनशन करने के लिए बाध्य होऊंगा। मेरी आपसे मांग है कि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 के चुनावों के पहले उस डीपीआर को स्वीकृत करें और बजट आबंटित करें। मेरे लोकसभा क्षेत्र में तीन सौ से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों का विद्युतीकरण किया जाए।